8. Biscripts (WP)
9. Hindi Busywriter
10. Devnagri (WP)
11. Aalekh (WP)

*WP—Word Processing Package
**DTP—Desk Top Publishing Packages

Radioactivity from phosphatic fertilisers

1635. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports of radioactivity from phosphatic fertilisers; and

(b) whether this report is based on a FAO document and if so, when was this released and when was this received by Government through its representative at FAO Rome; and

(c) what action has been or is proposed to be taken on the report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) There is no radioactive cadmium in phosphatic fertilisers as mentioned in the newspaper report. It is well known that all rock phosphates contain traces of urnium. However, they do not pose any health hazards during use.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

शीत भांडागार के नियम

1636. **श्री लक्खी राम अग्रवाल :**
श्री अजीत जोगी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार शीत भांडागार नियमों के संबंध में कोई विधेयक लाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो विधेयक को कब तक पुरःस्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को कुछ पहले इसी प्रकार का एक विधेयक प्राप्त हुआ था ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश सरकार से शीत भण्डारण विनियमन संबंधी एक विधेयक प्राप्त हुआ था । प्रस्ताव को इसलिए अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि उस समय देश में शीत भण्डारण विनियमन के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार शीत भण्डारण के लिए एक केन्द्रीय कानून लाने पर विचार कर रही थी। तथापि, बाद में इस विचार को त्याग दिया गया था । इसकी बजाय, केन्द्रीय सरकार ने एक "माडल विधेयक" तैयार किया था और इसे मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को परिचालित किया था जिसे आवश्यक संशोधन करके उनके द्वारा अपनाया जा सकता था । अब तक किसी भी राज्य सरकार ने आवश्यक कानून नहीं बनाया है ।

व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय सूचना परिषद् का गठन

1637. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रैस परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि समुचित मीडिया नीति तैयार करने के लिए एक व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय सूचना परिषद् का गठन किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और